Vol 5 Issue 1 Feb 2015

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

Indian Streams Research Journal
ISSN 2230-7850
Impact Factor : 3.1560(UIF)
Volume-5 | Issue-1 | Feb-2015
Available online at www.isrj.org

मुस्लिम शिक्षा की चुनौतियां

सरोज राय

सहायक प्रोफेसर शिक्षा विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

सारांश : शिक्षा का महत्व सर्वविदित है। यह किसी भी व्यक्ति समाज अथवा राष्ट्र के विकास का प्रमुख कारक होती है या यूं भी कहा जाना कि किसी की असली प्रगति का बैरोमीटर उसी शिक्षा से ही होती है। जिसकी बदौलत कोई राष्ट्र अपने मान से साधनों का समुचित विकास करने तथा उसकी सहायता से नवीनतम ज्ञान विज्ञान भौतिक समृद्धि यहां तक कि अध्यात्मिक उन्नति में भी मनचाही प्रगति हासिल कर सकता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्, शिक्षा आयोग (१९६४-६६) के अनुसार ''भारत के भाग्य का निर्माण अब उसकी कक्षाओं में हो रहा है।''

प्रस्तावनाः—

शिक्षा पूर्व के युगों की भांति समाज के कुलीन वर्गों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए जन्म अधिकार का विषय हो चुकी है। शायद यही राष्ट्रीय हितों के अनुकूल भी है। प्रत्येक राष्ट्र के पास योग्यता और प्रतिभा का एक निश्चित भण्डार होता है, जिसकी रचना उसके नागरिकों की प्रतिभा योग्यता और कार्य कुशलता द्वारा होती है। यदि कोई देश अपना पूर्ण विकास चाहता है तो उसे अपने समस्त नागरिकों का बिना किसी भेद-भाव के शिक्षित करना होगा। भारत जैसे देश में जहां विभिन्न जातिया, धर्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक निवार करते हैं, वहां की सरकारों के लिए यह आवश्यक हो जाता है। देश में राजनैतिक, सामाजिक स्थिरता शान्ति और अमन चैन कायम रखने के लिए विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों को समर्थन और संरक्षण प्रदान करे, तथा उनके मान-सम्मान का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़े। इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी, और तनाव की गुंजाइश कम रहेगी। सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी यही उचित है।

मुस्लिम शिक्षा की वर्तमान स्थिति :

अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग तालिमी दौड़ में काफी पिछड़े और वंचित है। समाज के इन्साफ और समानता के लिए ऐसे वर्गों की तालीम पर पूरा ध्यान दिया जाय। संविधान में शिक्षा उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति की हिफाजत करने तथा अपनी शैक्षिक संस्थाएं कायम करने के कुछ अधिकार दिए गये है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ अल्पसंख्यक समुदाय शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए है। सामाजिक न्याय तथा समानता के लिए इन समूहों में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। अपनी भाषा संस्कृति के संरक्षण के लिए अपने विद्यालयों को स्थापित करने के लिए अवसर देकर संविधान की गारन्टी का पालन किया जायेगा। मूल पाठ्यक्रम के साथ-साथ पाठ्य-पुस्तके, विद्यालयी गतिविधियों को सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समेकित आधार प्रदान किया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में मुस्लिम समुदाय के प्रति जो भी प्रयास किया गया उनमें भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का आंकलन करने के लिए न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन था। इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि यद्यपि मुसलमानों के बंधन की स्थिति प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, फिर भी आजादी के बाद भी देश में धार्मिक अलपसंख्यकों की दशा के विश्लेषण हेतु कोई योजनाबद्ध प्रयास नहीं हुआ। सच्चर समिति का गठन प्रधानमंत्री

मनमोहन सिंह के कार्यकाल में २००५ में किया गया। जिसका विषय था- ''हिन्दूस्तान के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करना।'' समिति ने अपनी रिपोर्ट २००६ में भारत सरकार को सौंप दी जो इस प्रकार हैं-

१.सन् २००१ के आंकड़ों के आधार पर मुस्लिम समुदाय में साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से नीचे पायी गयी।
२.सामान्य तौबा पर मुसलमानों तथा सामान्य औसत के बीच साक्षरता का अन्तराल नगरीय क्षेत्र और महिलाओं में अपेक्षाकृत अधिक है।
३.वर्तमान में विद्यालय न जाने वाले बच्चों के आंकड़ों से पाया गया कि ६-१४ आयु वर्ग के कुल मुस्लिम बच्चों में २५ प्रतिशत ऐसे हैं, जो कभी स्कूल गये ही नहीं, या बीच में ही पढाई छोड़ दिए।
४.स्कूल शिक्षा स्तर पर मुस्लिम बच्चों का उपलब्धि स्तर अन्य धार्मिक समुदायों के बच्चों की अपेक्षा काफी नीचे है।
५.सन् २००१ की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किए गए एक विश्लेषण में पाया गया कि १७ साल अथवा उससे ऊपर की आयु के ऊंपर मैटिकुलेशन की शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों में मुस्लिम बच्चों का अनुपात १७ प्रतिशत था जबकि अन्य समूहों में १६ प्रतिशत था।
६.प्राथमिक मिडिल, हायर सैकेण्डरी इन तीनों शिक्षा स्तरों पर पाठ्यक्रम पूरा करने से पूर्व ही विद्यालय छोड देने की मुस्लिम बच्चों में अनय सभी समुदायों की अपेक्षा अधिक पायी गयी।
७.उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मामलों में हमारे देश का एक बड़ा भाग अब भी वंचित है, और इसमें भी मुस्लिम समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सन् २००१ की जनगणना के अनुसार २० वर्ष और उससे ऊपर की कुल आबादी के लगभग ७ प्रतिशत लोग ग्रेजुएट अथवा डिप्लोमा होल्डर थे जब कि मुसलमानों में यह अनुपात ४ प्रतिशत से भी कम पया गया।

पोस्ट-ग्रेजुएशन स्तर पर भी लगभग ऐसी ही निराशाजनक स्थिति पाई गयी और प्रत्येक २० विद्यार्थियों में से केवल एक छात्र मुसलमान पाया गया फिर भी मुस्लिम विद्यार्थियों का सर्वाधिक रूझान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की नेशनल सैम्पल सर्वे कारकों के आधार पर कमेटी ने कहा है कि शैक्षिक उपलब्धि पर गरीबी को प्रभाव स्पष्ट रूप से पाया गया। शैक्षिक उपलब्धि पर प्रमुख अभिसूचक उस विद्यालय का स्तर भी होता है जिसमें छात्र पढ़ता है, कारण शिक्षा की गुणवत्ता और लागत विद्यालय के प्रभाव पर पड़ती है। इस दृष्टि से विभिन्न सामाजिक धार्मिक समुदायों में कोई अन्तर नहीं पाया गया। मुस्लिम समुदाय के बच्चे कम खर्चीले सरकारी अथवा सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पाये गये।
८.प्रारम्भिक स्तर पर उर्दू माध्यम विद्यालयों का बेहतर प्रावधान किया गया है, साथ ही साथ अंग्रेजी की पढाई के भी अवसर उपलब्ध करवाए गये हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, कि देश में उर्दू मातृ भाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाए देने का अवसर प्रदान करे। किन्तु इस संवैधानिक प्रावधान तथा विभिन्न कमेटियों की सकारात्म संस्तुतियों के बावजूद भी सच्चर कमेटी ने पाया कि उर्दू की शिक्षा हेतु हमारे देश के कई राज्यों में सुविधाओं का अभाव है।
९.राज्य स्तरीय आकलनों के अनुसार सामान्यतौर पर मुसलमानों तथा सामान्य औसत के बीच साक्षरता का अन्तराल नगरीय क्षेत्रों और महिलाओं में अपेक्षाकृत मुस्लिम महिलाएं राज्य की औसत साक्षरता से काफी नीचे है।
१०.मुस्लिम समुदाय भारतवर्ष का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है जो देश की कुल आबादी का १३.४ प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि सुधार कैसे किया जाए।
११.१४ वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सरकार का दायित्व है। इस दायित्व की पूर्ति न केवल मुस्लिमों की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए बल्कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से सभी वंचित बच्चों स्कूली पाठ्य पुस्तकों से पूर्वाग्रहों को दूर करना इसके लिए एक ऐसी प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता है जो पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करे और ऐसी विषय सामग्रियों को हटाए जो अनुपयुक्त हो तथा धार्मिक असहनशीलता प्रदान करती है।
१२.यह नितान्त आवश्यक है गरीब मुहल्लों व बस्तियों में सार्वजनिक अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की जाय जहां पर सरकार के अलावा गैर सरकारी संगठन और कारपोरेट जगत भी सहयोग प्रदान करें।
१३.सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ऊंची गुणवता वाले सरकारी विद्यालय स्थापित किये जाये।
१४.लड़कियों के लिए विशेष रूप से नवीं से बारहवी कक्षा हेतु अलग से विद्यालयों की व्यवस्था की जाये और सह-शिक्षा वाले स्कूलों में शिक्षाकाओं की अधिक संख्या में नियुक्ति की जाये।
१५.सभी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों की सुविधा प्राथमिकता के आधार पर करायी जाए तथा विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों के लिए यह सुविधा हर आकार के शहरों में की जानी चाहिए।

चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के आगरा में एक गैरसरकारी संगठन मुस्लिम महिलाओं को उनके मताधिकार की कीमत समझाने में दिन-रात जुटा रहा था। इसके अध्यक्ष सिराज कुरैशी का मानना है कि मुस्लिम पुरूष तो बड़ी तादाद में वोट डालते रहे हैं, पर महिलाएं अधिक संख्या में नजर नहीं आती। वे किसे वोट दें, इस पर चर्चा न होकर उनका सरोकार यह सुनिश्चित करना रहा कि मुस्लिम महिलाएं अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें।

दरअसल मुस्लिम महिलाओं को शैक्षिक व आर्थिक स्तर पर सशक्ति बनाने के अलावा राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए भी अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत है। मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का मसला काफी अहम है। सरकारी रपटों के मुताबिक मुस्लिम महिलाएं देश के निर्धनतम, शैक्षिक स्तर पर पिछड़े, राजनीति में हाशिए पर रहने

वाले समुदायों में से एक है।

१९८३ की अल्पसंख्यक रिपोर्ट (जो गोपाल सिंह कमेटी रिपोर्ट से जानी जाती है) में भी मुस्लिम लड़कियों की निराशाजनक शैक्षणिक स्थिति की और इशारा किया गया था। इसी तरह सच्च कमेटी की रिपोर्ट में यह उल्लेख किय गया था कि एक तो कर्ज जैसी सुविधाओं तक मुस्लिम महिलाओं की पहुंच बहुत कम होती है, इसके अलावा कर्ज वितरण में उनके साथ भेदभाव भी किया जाता है। इस भेदभाव के पीछे कर्जदाता संस्थानों के अधिकारियों की तंग सोच के अलावा उन महिलाओं का कम शिक्षित होना, अपने हक को हासिल करने के लिए मजबूती से स्टैंड न लेना आदि वजहें हो सकती हैं।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ साल पहले राज्यों के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्षों को संबोधित करते हुए मुस्लिम समुदाय में खासकर लड़कियों की शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर बल दिया था। उन्होंने मुस्लिम बहुल आबादी वाले जिलों व ब्लॉक्स में मुस्लिम लड़कियों के लिए सेंकडरी स्कूल खोलने की योजनाओं पर अमल के साथ ही उनके लिए मेडिकल व इंजीनियरिंग जैसी व्यसायिक शिक्षा का दायरा बढ़ाने की जरूरत को वक्त की मांग बतया था।

मुस्लिम औरतें गैर-मुस्लिम महिलाओं की तुलना में हर स्तर पर पिछड़ी हुई हैं। सवाल उन्हें मौका मिलने का है। हमारी राजनीतिक पार्टियों का यह दायित्व है कि वे मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को बिना मजहबी रंग दिए उठाएं और अपनी नीतियां भी इस बाबत जनता को बताएं। मुस्लिम महिलाओं की संसद व विधानसभाओं में भागीदारी भी बहुत कम है। चुनावी नारों में विकास-विकास की जो गूंज चारों तरफ सुनाइ पड़ रही है, उसमें मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को भी अगर जगह मिल सके तो बेहतर होगा।

मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों को सर्वशिक्षित करने के लिए आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर एक पृथक् मुस्लिम शिक्षा बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सके।

मुस्लिम शिक्षा बोर्ड को मूर्त रूप देने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है जो इस विषय में अपने सुझाव देगी तथा ईद के बाद वाकायदा इसका मसौदा तैयार किया जाएगा।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया हालांकि इस बोर्ड का पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, यह केवल मुस्लिम लड़के लड़कियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए किया गया है।

फिरंगी महली ने बताया कि मुस्लिम शिक्षा बोर्ड का गठन आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड की तज्र पर किया जाएगा जिसमें पिछड़े मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जाऐंगे और पढ़ाई का अच्छा माहौल तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मदरसों के छात्रों के लिए अंग्रेजी, हिन्दी और कम्प्यूटर शिक्षा पहले ही अनिवार्य की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इसी सप्ताह दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिल्ली काउंसिल, जमात-ए-इस्लामी आदि मुस्लिम संगठनों की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के लिए अलग से एक शिक्षा बोर्ड गठन करने की जरूरत महसूस की गई।

मौलाना फिरंगी महली ने कहा कि दिल्ली में हुए इस सम्मेलन में पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल एवं पूर्व अलपसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस बोर्ड के जरिए कक्षा १२ तक धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ अन्य सभी आधुनिक विषयों की बेहतर पढ़ाई पर निगरानी रखी जाएगी और मुस्लिम प्रबंधन की ओर से संचालित स्कूली और मदरसों में यह बोर्ड प्रभावी होगा।

डॉ. अंसारी ३१ अक्टूबर २००७ जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के दीक्षातं समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय मुस्लिम समुदाय सामाजिक विकास को अवरूद्ध करने वाले धार्मिक कर्मकाण्डों से छुटकारा पाने के लिए शिक्षा के महत्व को समझे।

देश में मुसलमानों की संख्या १५ करोड़ तक पहुचं चुकी है जो कि देश की कुल आबादी का १३.४ प्रतिश है। इनमें शहरीकरण का प्रतिशत भी सामान्य आबादी से ज्यादा है लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनमें साक्षरता की दर अन्य वर्गों की अपेक्षा कम है। देश की कुल मुस्लिम आबादी का तकरीबन चालीस फीसदी हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है।

ऐसी स्थिति में अज्ञानता और सामाजिक जड़ता जैसी इन बुराइयों को दूर करने के लिए मुस्लिम समाज को शिक्षा के महत्व पर ध्यान देना होगा तभी वह अन्य वर्गों के समकक्ष अपनी हैसियत बना सकेंगे।

निष्कर्ष :

देश में मुस्लिम शिक्षा के ढांचे को सुधारने व उनका स्तर उठाने के लिए केन्द्र सरकार जल्द १५ हजार करोड़ रूपये का विशेष अनुदान देगी। केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री के रहमान खान ने कहा कि भारतीय मुस्लिमों के लिए शिक्षा के ढांचे को सुधारने की जरूरत है। इसके लिए हम जल्द १०-१५ हजार करोड़ रूपये का विशेष फंड जारी करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ऑरिजिन के कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि भारतीय मुस्लिमों के पास संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन इसके लिए फंड उपलब्धा कराने के साथ बेहतर प्रबंधन की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिमों का स्तर सुधारने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी।

फिलहान उनके लिए उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर है, सिसे समाज में परिवर्तन आएगा। मुस्लिमों को अल्पसंख्यक के बजाए ये सोचना चाहिए कि वे भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में फंड का उपयोग बहुत धीमी गति से होता है, इसके लिए मुख्यमंत्रियों से बात की जाएगी।

आवश्यकात है उन्हें उचित प्रोत्साहन और अवसर प्रदान करने की। फिर देखिए वे कितनी ऊंची उड़ान भरती है। यदि बेटियां आगे बढेगी तो इससे आपके खान-दान और देश का ही नाम रोशन होगा इसलिए उड़ान भरने के पूर्व ही उनके पर न काटे। आखिर कब तक हम अपनी बेटियों को परदे में रखेंगे? क्या उन्हें अन्य समुदाय की लड़कियों की भांति पढ़ने-लिखने कैरियर बनाने और स्वच्छंद उड़ान भरने का कोई हक नहीं? मुस्लिम समाज को अपनी सोच बदलनी होगी तथा अपनी बेटियों को राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ना होगा, तभी ये लड़कियां बुलंदियों को छू सकेगी।

संदर्भ ग्रन्थ–सूची

1.कुरूक्षेत्र शिक्षा विशेषांक, सितम्बर (२००७), मासिक ग्रामीण विकास मन्त्रालय, नई दिल्ली।

2.भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका (जनवरी-जून, २०१३) सरस्वती कुन्ज निराला नगर, लखनऊ (२२६०३०) उत्तरप्रदेश।

3."Journal of Indian Education", NCERT, NEW Delhi, Feb. 2007.

4.''नया ज्ञानोदय'' भारतीय ज्ञानपीठ दिसम्बर, २००७।

5.भारत में शिक्षा का विकास (२००२), सुरेश भटनागर, संजय कुमार, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।

6.''समाज कल्याण, मुस्लिम समाज और लड़कियों का शैक्षिक पिछड़ापन'', सितम्बर, २००८, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की मासिक पत्रिका।

7.www.jagran.com...national-centre-mulis-us-3bn-fund-to give education-to muslim-10969079html.

8.www.ufhrews.in/newdelhi-16-d

9.wwwlivehindustan.com news/.../article7-story-39-39 131796.html

10.naidunia.jagran.com/..expert-comment-muslim-women-in india.78322

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org